**के० स० स्वा० सेवा औषधालयों का कार्य समय**

7755. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के० स० स्वा० सेवा के कुछ औषधालयों का कार्य-समय प्रातः 7 बजे से 1 बजे सायं और 1 बजे सायं से 7 बजे सायं कर दिया गया है जो कि कर्मचारियों और रोगियों दोनों के ही लिए सुविधाजनक है;

(ख) यदि हां, तो उन औषधालयों के नाम क्या हैं जिनमें यह कार्य-समय लागू कर दिया गया है; और

(ग) इस कार्य-समय को के० स० स्वा० सेवा के सभी औषधालयों में लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीहार रंजन लस्कर)** : (क) आजमायश के तौर पर थोड़े से औषधालयों में काम के संशोधित घंटे शुरू कर दिए गए है ।

(ख) काम के संशोधित घंटे निम्नलिखित पांच औषधालयों में लागू किए गये है :

1. वैलजली रोड
2. रामकृष्ण पुरम–1
3. जनकपुरी
4. किंग्सवे कैम्प
5. शाहदरा

(ग) अन्य यूनिटों में भी यह व्यवस्था शुरू करने सम्बन्धी निर्णय लेने से पहले इस प्रयोग के परिणामों को अभी कुछ देर और देखना होगा ।

**Economic burden of uneconomic Lines**

7756. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government propose that the economic burden on Railways on account of un-economic railway lines be passed on to the State Governments concerned; and

(b) if so, the response of State Governments in this regard?

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN)**: (a) and (b). The Railway Convention Committee recommended in July 1976 that if uneconomic branch lines are to be continued indefinitely in spite of recurring losses and with no possibility of their becoming viable, the authorities which desire these lines to be run should share with the Railways the unavoidable losses. In pursuance of this recommendation, the Railways made a critical and objective review of uneconomic branch lines and identified 23 lines as remiting closure. The State Governments concerned were approached in June 1978 for their concurrence to the closure of these uneconomic branch lines or to agree to re-imburse the losses incurred by the Railways in keeping them in operation. None of the State Governments from whom replies have been received so far has agreed either to the closure of the lines or to the re-imbursement of the losses to the Railways.